भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1481

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जेएसए:सीटीआर के तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं

1481. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) पहल के तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट रणनीतियां क्या हैं;

(ख) सरकार किस प्रकार स्थानीय समुदायों को उक्त पहल को लागू करने में शामिल करने की योजना बना रही है जिससे सतत जल प्रबंधन संबंधी प्रचलनों को बढ़ावा दिया जा सके और पुनर्भरण संरचनाओ का दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके;

(ग) सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और उक्त परिणामों को भावी योजना में किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यान्वयन करने और जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए जीआईएस मैपिंग और ओईओटी-आधारित निगरानीजै सी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों को संपूरित करती है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो मार्च से नवंबर तक वार्षिक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, यह अभियान में

जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर केन्द्रित होता है। इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कनवर्जेंट वित्तपोषण और सक्रिय जन भागीदारी पर जोर दिया जाता है। सरकार ने कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने, संसाधन अनुकूलन और संस्थागत समन्वय का लाभ उठाने वाली एक बहु-आयामी रणनीति कार्यान्वित की है। इस रणनीति का प्रमुख घटक समेकित संसाधन जुटाना है, जहां कई प्रमुख योजनाओं से निधियों को एकत्र किया जाता है जिससे सहयोग और इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इन योजनाओं में अन्य विधियों के साथ-साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक) और 15वां वित्त आयोग अनुदान की निधि शामिल रहती है। इससे जल संरक्षण प्रयासों में विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होता है।

इस दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए, जल संचय जन भागीदारी पहल को माननीय प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू किया गया था। जल संचय जन भागीदारी का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत में, एक मिलियन कम लागत वाली जल-पुनर्भरण संरचनाएं सृजित करना है, जिनमें वैज्ञानिक, तकनीक और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इस पहल में, स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करते हुए सक्रिय भागीदारी और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है जिसमें न केवल सरकारी योजनाओं से बल्कि उद्योग - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), मानव-सौहार्द, व्यक्तिगत दान-दाताओं, लोगों से धन जुटाना आदि जैसे तरीकों से धन जुटाया जाता है जिससे कि लोगों की भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों के साथ ही मानव-सौहार्द और कॉर्पोरेट संस्थाएं, इस पहल के प्रति सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इससे जल सुरक्षा संबंधी मामलों के निपटान में एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। इस पहल की सफलता से प्रेरित होकर, राजस्थान सरकार ने एक "कर्मभूमि से मातृभूमि" योजना शुरू की है, जो लोगों को उनके मूल क्षेत्रों में जल संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक साझेदार मंत्रालय/विभाग में केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों (सीएमएनओ) को नामित किया गया है जिससे निरंतर अंतर-मंत्रालयी सहयोग को सुलभ बनाया जा सके। प्राथमिकताओं को संरेखित करने और समन्वय को बढ़ाने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इनमें सचिव स्तर की बैठकें और अपर-सचिव एवं राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक की अध्यक्षता वाली बैठकें शामिल रहती हैं जिससे इसके कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर किया जा सके और मंत्रालयों के बीच संरचित सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मंत्रालयों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण प्रयासों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इससे

जल सुरक्षा की क्रॉस-सेक्टोरल प्राथमिकता सुनिश्चित होती है। इसमें कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के कार्यान्वयन की पारस्परिक सीखों और अभिनव प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रणालियों और सफल मॉडलों को साझा किया जाता है। इससे सरकार का समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के स्थायी और प्रभावशाली जल प्रबंधन समाधान सामने आते है, जो राष्ट्र की भूजल पुनर्भरण और दीर्घकालिक जल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक जिले और नगर निगम में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जल मिशन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के चार समर्पित अधिकारियों को राज्यों, मंत्रालयों, उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और तकनीकी एडवाइजरी दस्तावेज को राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से तैयार किया गया है और उन्हें सभी स्तरों पर हितधारकों की सहायता के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। इस पहल में जन-जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) जैसे कार्यकलाप भी किए गए हैं।

(ग): सरकार ने जल संरक्षण संरचनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जल शक्ति अभियान:कैच द रेन के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को शामिल करते हुए कई उपाय किए हैं जिसके कारण भूजल स्तर में सुधार हुआ है। केंद्रीय दलों को जिलों के क्षेत्रीय दौरे के लिए नियुक्त किया गया है जिससे कि जल शक्ति अभियान:कैच द रेन अभियान के कार्यान्वयन में लगे स्थानीय अधिकारियों के साथ सीधे-तौर पर बातचीत की जा सके। इन दलों में अपर-सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव रैंक के केंद्रीय नोडल अधिकारी और केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जैसे प्रमुख जल-संबंधी संगठनों के तकनीकी अधिकारी होते हैं। इन फील्ड दौरों से जल संरक्षण कार्यकलापों को कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का ऑन-ग्राउंड आकलन करने में मदद मिलती है और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस अभियान की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान:कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) विकसित किया गया है जो आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय मंच है। यह पोर्टल कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं सहित जल संरक्षण प्रयासों की नियमित ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। जल शक्ति अभियान:कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से फील्ड दौरों और आकंड़ों की निगरानी से प्राप्त अंतर्दृष्टियों से भावी जल संरक्षण प्रयासों की रणनीतियों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह, जल संचय जन भागीदारी डैशबोर्ड, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हितधारकों को प्रत्येक निर्मित पुनर्भरण संरचना की फोटो, जियो-टैगिंग और अन्य विवरणों के साथ ऑनबोर्ड करने के लिए प्रदान किया गया है। निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय

जल आयोग के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है जो समय पर अपडेट और आंकड़ों का सत्यापन सुनिश्चित करते हैं। इन नोडल अधिकारियों को आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 1% पुनर्भरण संरचनाओं की परीक्षण जांच करने और संबंधित जिलों/निगमों/नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय जल आयोग/केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और जिलों/निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यकलापों को सहयोग देने और निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल मिशन में एक समर्पित सेल स्थापित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण /नवीनीकरण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन राज्य सरकारों और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से किया जाता है। ये आवधिक आकलन भूजल पुनर्भरण, उपयोग के रुझानों और समग्र उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जो जल संसाधन प्रबंधन में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। जिला और राज्य स्तर की समीक्षा प्रणाली के साथ ही क्षमता निर्माण पहलों से निरंतर निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए भूजल संसाधनों का आकलन और निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी देखी गई है। टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाला पुनर्भरण वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर वर्ष 2024 में 25.34 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) हो गया, जो जल संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। जबकि ऐसा सुधार राज्य और केंद्रीय सरकारों के प्रभावी कार्यकलापों को उजागर करते हैं, भूजल स्तर में सुधार कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें वर्षा और जल प्रबंधन की कार्यनीति वाली प्रणालियां शामिल हैं।

(घ): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करें। देश भर के 705 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, जल शक्ति केंद्रों में जल संरक्षण के तरीकों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और ग्रे वाटर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी को प्रचारित करते हैं। ये केंद्र, स्थानीय समुदायों को इससे संबधित मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2019 से अब तक, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत 1,69,699 प्रशिक्षण कार्यक्रम/किसान मेलों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल मिशन ने टेलीविजन पर 'जस्ट जूनियर' श्रृंखला के प्रसारण, 'मिशन लाइफ' के प्रचार आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय जल मिशन ने जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए 58 जल चर्चाएं, 46 जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संवाद और विभिन्न प्रकार की अन्य कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हमारे देश की दो सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों, अर्थात हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस की

विनाइल रैपिंग के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ सहयोग किया। इन ट्रेनों ने जल संरक्षण, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का महत्वपूर्ण संदेश दिया है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोगों के बीच जल संरक्षण का संदेश को विस्तारित करने के लिए सूचना शिक्षा, संचार संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं। विभाग की सोशल मीडिया टीम नियमित रूप से जल संरक्षण संबंधी जानकारी की पोस्ट तैयार करती है और मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं को विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रमुखता देती है। इसके अलावा, मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्ति भी नियमित रूप से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ साझा की जाती है।

(ङ): राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन को कार्यान्वित किया गया है जिसके अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के प्रभाव को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची तैयार करना है जिससे वैज्ञानिक रूप से जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे पुराने राजस्व रिकॉर्डों, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी से रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण तकनीक का उपयोग करते हुए जल निकायों की गणना करें, इसकी सीमाओं को चिह्नित करें, संरचनाओं की जियो-टैगिंग करें और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र तथा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणालियों के आंकड़ों को एकत्र करें। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक रूप से आंकडा-आधारित संरक्षण योजनाओं के विकास को सक्षम बनाया जाता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) के अनुसार, 619 जिलों ने पहले से ही ऐसी योजनाएं बना ली हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसमें लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के जलभृत्तों के मानचित्रण में जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इन मानचित्रों से भूजल पुनर्भरण और सतत जल प्रबंधन में आवश्यक जल-भूवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि हासिल होती है।

*****